उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 | अंक 21 | 1-15 नवंबर 2021 | ₹ 20/-

महाराष्ट्र में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा दंगे भड़काने का प्रयास

- स्वामी श्रद्धानन्द के हत्यारे को महिमामंडित करने का अभियान
- इमरान सरकार ने इस्लामिक संगठन के सामने घुटने टेके
- इराक के प्रधानमंत्री की हत्या करने का प्रयास
- मुस्लिम विश्वविद्यालय से इकबाल का संबंध

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा दंगे भड़काने का प्रयास 04
स्वामी श्रद्धानन्द के हत्यारे को महिमामंडित करने का अभियान 07
तस्लीम रहमानी का पॉपुलर फ्रंट से त्यागपत्र 09
अफगानिस्तान पर सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 11
वक्फ भूमि घोटाले में नवाब मलिक घेरे में 14

विश्व

इमरान सरकार ने अतिवादी इस्लामिक संगठन के सामने घुटने टेके 16
अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के 600 आतंकी गिरफ्तार 18
काबुल अस्पताल में धमाके में 20 मरे 19
बलूचिस्तान में पृथकतावादी सक्रिय 20
म्यांमार में इस्लामिक आतंकियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की तैयारी 21

पश्चिम एशिया

इराक के प्रधानमंत्री की हत्या करने का प्रयास 22
इथियोपिया में विद्रोह 23
अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को अस्त्र-शस्त्रों की सप्लाई 24
इजरायल ईरान के साथ युद्ध के लिए तैयार 24
सऊदी अरब में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान 26

अन्य

मुस्लिम विश्वविद्यालय से अल्लामा इकबाल का संबंध 27
मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोगो से संबंधित नोटिस 27
सऊदी अरब में रोजगार का स्वदेशीकरण 28
बढती आबादी के लिए मुल्क के मदरसे जिम्मेवार 29
बलात्कार के आरोपी को नपुंसक बनाना इस्लाम के खिलाफ 29

सारांश

देश के कई राज्यों में चुनाव की धमक शुरू होते ही मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कुछ अतिवादी मुस्लिम संगठन सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उर्दू समाचारपत्रों ने त्रिपुरा की घटना की आड़ लेकर देश भर मं भाजपा के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान में उन्हें कांग्रेस, वामदलों और अन्य सेक्युलरवादी लोगों का समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र के एक विवादित सुन्नी संगठन रजा एकेडमी ने हाल ही में राज्य के विभिन्न नगरों में बंद के आयोजन की घोषणा की थी। इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उग्र भीड़ ने पुलिस और सार्वजनिक संपत्ति को अपना निशाना बनाया। राज्य के आधे दर्जन शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। विश्व हिंदू परिषद ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए रजा एकेडमी और अन्य अतिवादी मुस्लिम संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। त्रिपुरा सरकार ने अधिकृत रूप से कहा है कि वहां पर उग्र प्रदर्शनों के कारण कोई भी मस्जिद क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। मगर इस कथित घटना की आड़ लेकर देश भर के मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है।

स्वामी श्रद्धानन्द देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, आर्यसमाजी नेता, शिक्षविद और शुद्धि आंदोलन के प्रणेता थे। खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधो ने हिंदू मुस्लिम एकता का जो अभियान चलाया था उसके फलस्वरूप स्वामी श्रद्धानन्द को दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में नमाजियों को संबोधित करने का अवसर मिला। मगर जब उन्होंने विदेशी आक्रांताओं द्वारा जबरन मुसलमान बनाए गए हिंदुओं के लिए घर वापसी का 'शुद्धि अभियान' शुरू किया तो मुसलमान उनकी जान के दुश्मन बन गए। एक धर्मांध मुसलमान अब्दुल रशीद उनके निवास स्थान में घुसा आर चाकू से स्वामी श्रद्धानन्द के शरीर को छलनी करके उनकी हत्या कर दी। न्यायालय ने उसे फांसी की सजा दी। हालांकि उसके मुकदमे को लड़ने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और सर इकबाल तक न्यायालय में पेश हुए थे। अब्दुल रशीद को दिल्ली की जेल में फांसी देने के बाद दिल्ली गेट पर स्थित कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कई दशक गुजर गए मगर अब्दुल रशीद की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मगर पिछले छह वर्ष से कुछ अतिवादी मुस्लिम नेताओं ने अब्दल रशीद को गाजी और इस्लाम तथा रसूल का फिदाई घोषित करके उसके उर्स को मनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। क्या एक हत्यारे को महिमामंडित करना उचित ठहराया जा सकता है?

इमरान सरकार को पाकिस्तान के एक अतिवादी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के सामने घटने टेकने पड़े हैं। इस संगठन का संबंध बरेलवी संप्रदाय से बताया जाता है। यह संगठन पाकिस्तान में शरिया हुकूमत को लागू करने और रसूल और इस्लाम की तौहीन करने वालों को सरेआम मौत की सजा देने का समर्थक है। कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान के काले कानून ईशनिंदा के तहत एक ईसाई महिला आसिया बीबी को मौत की सजा दी गई थी। जब इस फैसले के खिलाफ विश्व भर में हंगामा मचा तो पाकिस्तान सरकार ने आसिया बीबी को माफ करके एक विशेष हवाई जहाज से यूरोप के एक देश में भिजवा दिया। इस फैसले के खिलाफ इस संगठन ने लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद को घेरने की घोषणा की थी। पाकिस्तान सरकार ने इस अतिवादी इस्लामिक आंदोलन को पहले तो ताकत से कुचलने की कोशिश की मगर बाद में जनता के रूख को देखते हुए इस अतिवादी इस्लामिक संगठन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है।

महाराष्ट्र में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा दंगे भड़काने का प्रयास

त्रिपुरा में कथित हिंसा के खिलाफ विवादित इस्लामिक संगठन रजा एकेडमी ने महाराष्ट्र में बंद और विरोध प्रदर्शनों का जो सिलसिला शुरू किया था उसने हिंसक रूप ले लिया है और राज्य के पांच प्रमुख नगरों में दंगे भड़क उठे हैं। इन दंगों में आगजनी और लूटपाट की भी घटनाएं हुई हैं। इस पर अनेक नगरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 100 के लगभग दंगाईयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने सरकार से मांग की है कि इन दंगों को भड़काने वाले संगठन रजा एकेडमी पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया है कि वे दंगा भड़काने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएं। महाराष्ट्र के अनेक मुस्लिम बहुल नगरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है।

इत्तेमाद (15 नवंबर) के अनुसार महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वाल्से पाटिल ने कहा है कि हिंसा से प्रभावित अमरावती नगर में स्थिति नियंत्रण में है। यहां पर लगातार दो दिनों की हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में महाराष्ट्र में निकाली गई रैलियों के संबंध में पुलिस विस्तृत जांच करेगी और इनमें हुए नुकसान का भी पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रजा एकेडमी हो या कोई अन्य संगठन उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि का भी पता लगाया जाएगा। शुक्रवार को महाराष्ट्र के अनेक नगरों में हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा की शुरुआत त्रिपुरा में मस्जिदों पर हुए कथित हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और बंद से हुई थी।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि मालेगांव और नांदेड में हालात नियंत्रण में थे मगर अमरावती में भाजपा द्वारा आयोजित बंद के दौरान हिंसक घटनाएं हुईं। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें अनेक लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने अनेक स्थानों पर पथराव किया। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और

कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रही है। राज्य सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए पुलिस महानिदेशक के दर्जे के चार उच्चाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया है। यह निर्णय उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया है।

त्रिपुरा में हुई कथित हिंसा के बाद मुस्लिम संगठनों ने जो बंद का आयोजन किया था उसके जवाब में अगले दिन भाजपा ने बंद का आयोजन किया, जिसमें पथराव की कई घटनाएं हुईं। मुस्लिम संगठनों की अपील पर अमरावती, नांदेड, मालेगांव और यवतमाल आदि कई नगरों में रैलियां निकाली गईं। हिंसा फैल जाने के कारण अमरावती जिले के पांच अन्य स्थानों पर भी कर्फ्यू लगाया गया है। हिंसा और पथराव की घटनाओं के सिलसिले में अमरावती में पुलिस ने 50 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक उच्च पुलिस अधिकारी के अनुसार कर्फ्यू को अब अमरावती जिले के कई और स्थानों पर बढ़ा दिया गया है। जिला के संरक्षक मंत्री यशोमति ठाकुर के अनुसार रविवार को अमरावती में स्थिति शांतिपूर्ण रही क्योंकि राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) की आठ बटालियनों के अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। राज्य सरकार ने पुणे में धारा 144 लागू कर दी है।

इत्तेमाद (15 नवंबर) के अनुसार विश्व हिंदू परिषद ने एक संवाददाता सम्मेलन में महाराष्ट्र सरकार से रजा एकेडमी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंट करेगा। जबकि कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने रजा एकेडमी के साथ-साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (15 अक्टूबर) के अनुसार मुंबई के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों भिंडी बाजार, डोंगरी, नल्ल बाजार और जेजे मार्ग पर सशस्त्र पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और किसी तरह की अफवाह और सोशल मीडिया पर किए जा रहे दुष्प्रचार का शिकार न बनें।

बुलढाना से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां पर रजा एकेडमी की अपील पर हुए हड़ताल और धरना के बाद कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में रजा एकेडमी के पदाधिकारियों सहित 350 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि हिंदू संगठनों द्वारा सोशल मीडिया पर मुस्लिम विरोधी ट्विट और फेसबुक पर शरारतपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। योगी देवनाथ ने महा विकास आघाडी को महा विनाश आघाडी की संज्ञा दी है और उसे अमरावती के दंगों के लिए दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा का बहाना बनाकर मजहबी जुनूनियों ने नांदेड, मालेगांव और अमरावती में जिहाद का खौफनाक चेहरा दिखाया है। जिहादी दो दिन से महाराष्ट्र में दंगा भड़का रहे हैं और मीडिया खामोश है। रजा एकेडमी एक आतंकवादी संगठन है जो कि प्रदेश में हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। मालेगांव में हिंसा भड़काने के आरोप में पांच मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इस सिलसिले में अब तक 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है जबकि दस अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। दंगों की जांच के लिए पांच टीमें गठित की गई हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (15 नवंबर) के अनुसार मुफ्ती मंजूर जियाई ने महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील की है कि वे हर कीमत पर शांति बनाए रखें। उन्होंने अभिभावकों से कहा है कि वे अपने बच्चों की निगरानी करें ताकि वे किसी गैरकानूनी गतिविधि में भाग न ले पाएं।

इससे पूर्व **मुंबई उर्दू न्यूज** ने 13 नवंबर के अंक में मख्य पृष्ठ पर इस बंद के बारे में तीन समाचार प्रकाशित किए थ, जिनमें यह दावा किया गया था कि मुंबई और महाराष्ट के अनेक जिलों

में मुस्लिम संगठनों द्वारा आयोजित बंद पूरी तरह से सफल रहा है और रजा एकेडमी ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजकर यह मांग की है कि त्रिपुरा में दंगा भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नांदेड में बंद के दौरान हिंसा हुई और कई स्थानों पर जुलूस पर पथराव हुआ जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें पांच पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। मालेगांव में आगरा रोड़ पर स्थित अनेक दुकानों में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया जिस पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में अनेक लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों को भी पीटा। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि कुछ जज्बाती नौजवानों ने कानून का उल्लंघन करने का प्रयास किया था मगर पुलिस और मुस्लिम नेताओं के हस्तक्षेप से दंगे नहीं भड़के।

औरंगाबाद टाइम्स (13 नवंबर) के अनुसार औरंगाबाद में बंद पूरी तरह से सफल रहा। जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद नहीं की थीं उन्हें युवकों ने फूलों के हार पेश करके दुकानों को बंद करवाया। चम्पा चौक पर युवकों ने उग्र प्रदर्शन करने का प्रयास किया। मगर पुलिस ने इसे विफल बना दिया। समाचारपत्र ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में आयोजित बंद का सभी मुस्लिम संगठनों जैसे- अहले सुन्नत, जमात-ए-इस्लामी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी, जमीयत उलेमा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदि ने समर्थन करने की घोषणा की है।

औरंगाबाद टाइम्स (15 नवंबर) ने यह दावा किया है कि मुस्लिम जमातों की अपील पर पूरे महाराष्ट्र में बंद का आयोजन किया गया था। लेकिन अमरावती, नांदेड और मालेगांव में हिंसक घटनाएं हुईं। कुछ स्थानों पर आग लगाई गई और पथराव किया गया। अमरावती में मुसलमानां पर पुलिस ने लाठीचाज किया और नांदेड में प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां चलाईं। मालेगांव में भीड़ ने पुलिस पर बोतलें फेंकी जिसके कारण कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

इत्तेमाद (13 अक्टूबर) के अनुसार नांदेड में हैदरबाग रोड़ पर मुसलमानों ने धरना दिया। इस धरने को मुस्लिम मजलिस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाडी का भी समर्थन प्राप्त था। धरने में हजारों मुसलमानों ने भाग लिया। जब प्रदर्शनकारी वापस जा रहे थे तो कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे कुछ पुलिस वाले घायल हो गए और अनेक वाहनों को भी नुकसान पहुंचा।

इत्तेमाद ने 15 नवंबर के संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा सरकार गठन करने में विफल रही है इसलिए वह अब त्रिपुरा की घटना की आड़ लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि मुस्लिम जमातों के बंद के जवाब में अगले दिन भाजपा ने बंद का आयोजन किया जिसमें हिंसा भड़क उठी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि भाजपा जानबूझकर महाराष्ट्र में हिंसा को भड़का रही है ताकि सत्तारूढ़ गठबंधन को अस्थिर किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम हिंसा भड़काने वालों को बेनकाब करके ही दम लेंगे।

हमारा समाज (15 नवंबर) के अनुसार रजा एकेडमी के प्रमुख मोहम्मद सईद नूरी ने राज्य सरकार द्वारा हाल में हुए दंगों की जांच का स्वागत किया है और कहा है कि जांच बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए ताकि यह सच्चाई सामने आ सके कि राज्य में हिंसा भड़काने वाले कौन थे।

टिप्पणी : हाल ही में महाराष्ट्र में हुए दंगों के कारण एक बार फिर बरेलवी सुन्नी मुसलमानों का संगठन रजा एकेडमी चर्चा का केंद्र बना हुआ

है। इस संगठन की स्थापना 1978 में एक मुस्लिम उलमा मोहम्मद सईद नूरी ने की थी और 1986 से वे इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। यह संगठन बरेलवी संप्रदाय से संबंधित विभिन्न इस्लामिक मुद्दों पर लिखी हुई पुस्तकों को उर्दू, अरबो और अंग्रेजी में प्रकाशित करता है। यह संगठन अगस्त 2012 को तब चर्चा में आया था जब असम और रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए कथित अत्याचारों के खिलाफ इसने मुंबई के आजाद मैदान में एक उग्र प्रदर्शन का आयोजन किया था। इसके बाद मुंबई में दंगे भड़क उठे। अनेक वाहनों को आग लगा दी गई। बसों और वाहनों पर पथराव किया गया। पुलिस के दावे के अनुसार कम-से-कम पांच महिला पुलिसकर्मियों के साथ भीड़ ने दुर्व्यवहार किया और पुलिस पर हमला करके अनेक लोगों को घायल कर दिया। आजाद मैदान में देश के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में जो अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है उसे भी मुसलमानों की भीड़ ने नुकसान पहुंचाया। बाद में अब्दुल कादिर अंसारी नामक एक व्यक्ति को इस आरोप में पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने इन दंगों के सिलसिले में 80 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना अतहर, रजा एकेडमी के सईद नूरी आदि शामिल थे। फरवरी 2021 में रजा एकेडमी ने बीबीसी द्वारा पैगम्बर मोहम्मद का चित्र प्रकाशित करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर बीबीसी को माफी मांगनी पड़ी थी। 2016 में जाकिर नाइक पर कार्रवाई किए जाने का भी इस संगठन ने विरोध किया था। 2006 में भिवंडी में रजा एकेडमी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी।

स्वामी श्रद्धानन्द के हत्यारे को महिमामंडित करने का अभियान

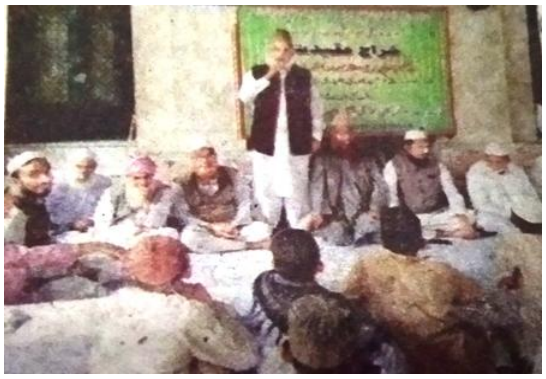

आर्य समाजी नेता और महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानन्द के हत्यारे को महिमामंडित करने का अभियान राजधानी के कुछ कट्टरवादी मुस्लिम नेता गत कुछ वर्षों से चला रहे हैं।

एक धर्मांध मुसलमान अब्दुल रशीद ने 1926 में स्वामो श्रद्धानन्द के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। बाद में उसे फांसी की सजा दी गई। उसके बाद उसे दिल्ली के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। खास बात यह है कि देश के विभाजन तक किसी भी मुस्लिम नेता में उसे महिमामंडित करने की हिम्मत नहीं हुई। उसे महिमामंडित करने का सिलसिला पिछले सात वर्षों से शुरू हुआ है। जिस दिन उसे फांसी दी गई थी इस्लामिक संगठनों द्वारा उस दिन को उर्स के रूप में मनाया जाता है। इस्लामिक परंपराओं के अनुसार उर्स सिर्फ प्रमुख मुस्लिम पोरों, उलेमाओं का ही मनाया जाता है।

इस बार भी राजधानी के उर्दू समाचारपत्रों में अब्दुल रशीद के उर्स मनाने की चर्चा काफी दिनों से शुरू हो गई थी। अजीब बात यह है कि उसे इस्लाम के लिए आत्मबलिदान करने वाले गाजी की संज्ञा दी गई है।

इंकलाब (15 नवंबर) में अब्दुल रशीद के उर्स के समाचार को चित्र सहित तीन कॉलमी समाचार के रूप में प्रकाशित किया गया है। जबकि एक अन्य समाचारपत्र रोजनामा सहारा में भी इसी समाचार को तस्वीर सहित चार कॉलमी

समाचार के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसके अतिरिक्त कई अन्य उर्दू समाचारपत्रों ने इस समाचार को प्रकाशित किया है।

इंकलाब ने इसे आशिक-ए-रसूल की संज्ञा दी है और कहा है कि मस्जिद भूली भटियारी में एक समारोह का आयोजन करके अब्दुल रशीद को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने कब्रिस्तान में जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए सामुहिक रूप से फातिहा भी पढ़ा। भूली भटियारी मस्जिद के प्रबंधक हाजी अमीनुद्दीन ने कहा है कि "गाजी अब्दुल रशीद ने पैगम्बर की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया। यह उसके जज्बा ईमानी और अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत और यकीदत का संकेत है। जब बार-बार चेतावनी देने पर भी वह गुस्ताख रसूल (स्वामी श्रद्धानन्द) बाज नहीं आया तो रसूल और इस्लाम के खातिर रशीद ने उसकी (स्वामी श्रद्धानन्द की) हत्या कर दी जिस पर उसे फांसी की सजा हो गई और वह शहीद का दर्जा पा गया।" दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य चौधरी शरीफ अहमद ने कहा कि गाजी अब्दुल रशीद ने रसूल की खातिर जो कदम उठाया था वह इस्लाम के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस समारोह में भाग लेने वालों में मुफ्ती इशाक कासमी, शकील रशीन, मौलाना ऐजाज अहमद कासमी, मौलाना अबु बकर मुजाहिरी, मौलाना अहमद अली कासमी, हाजी मुईनुद्दीन अहमद, हाफिज इरफान, अब्दुल हादी और मोहम्मद कामरान ने भी अब्दुल रशीद को श्रद्धांजलि दी। बाद में दिल्ली गेट कब्रिस्तान में जाकर रशीद की कब्र पर फातिहा पढ़ा गया।

रोजनामा सहारा (15 नवंबर) के अनुसार 1991 में गाजी अब्दुल रशीद के नाम पर दिल्ली गेट में एक मदरसा स्थापित किया गया था जो कि अब भी बच्चों को दीनी तालिम दे रहा है। इस उर्स में जमीयत उलेमा दिल्ली के महामंत्री हाजी मोहम्मद असद मियां, जमील अंजुम आदि अनेक मुस्लिम नेताओं ने भी हिस्सा लिया।

कौन थे स्वामी श्रद्धानन्द?

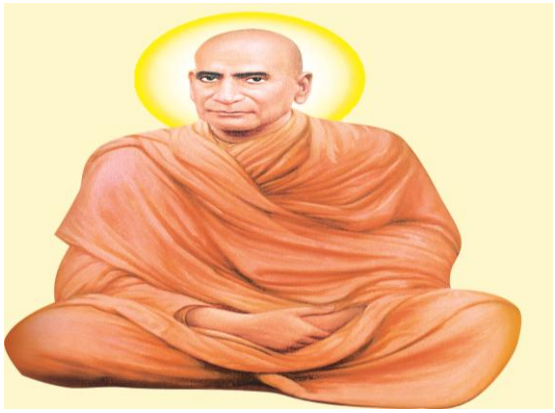

स्वामी श्रद्धानन्द की गणना देश के चोटी के स्वतंत्रता सेनानियों, आर्य समाजी नेताओं और शुद्धि आंदोलन को प्रारम्भ करने वालों में होती है। वे विख्यात आर्य समाजो शिक्षा संस्थान गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक थे। उनका जन्म पंजाब के जालंधर जिले में हुआ था और उनके पिता उत्तर प्रदेश में पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनका प्रारंभिक नाम महात्मा मुंशीराम था। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रभाव में आकर उन्होंने घर त्याग दिया और वे सन्यासी बन गए। उनका नया नाम स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती रखा गया। वे एक मात्र ऐसे हिंदू नेता हैं, जिन्हें दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण देने का अवसर मिला था। उन दिनों वे खिलाफत आंदोलन में काफी सक्रिय थे और गांधी जी के सेक्युलरवाद के प्रभाव में आकर उन्होंने खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था और हिंदू मुस्लिम एकता की लहर को सुदृढ़ करने के लिए जामा मस्जिद में नमाजियों को संबोधित करने में सफल रहे थे। 1923 में उन्होंने धर्मांतरण द्वारा मुसलमान बनाए गए लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का गठन किया था। उनक प्रयासों से एक लाख 63 हजार मलकाना राजपूत इस्लाम छोड़कर पुनः हिंदू बने थे। इसके

साथ ही उनका कट्टरवादी मुसलमानों से विरोध शुरू हो गया।

1926 में जब स्वामी श्रद्धानन्द बीमार पड़े तो एक 22 वर्षीय धर्मांध मुसलमान अब्दुल रशीद दिल्ली के नया बाजार स्थित उनके निवास स्थान में घुसा और उसने चाकू से स्वामी जी की हत्या कर दी। बाद में न्यायालय ने इस आतंकवादी को फांसी की सजा दी थी। इसको बचाने के लिए जिन लोगों ने उसका मुफ्त मुकदमा लड़ा था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और सर इकबाल दोनों ही शामिल थे।

शुद्धि सभा के जवाब में तब्लीगी जमात का जन्म हुआ। तब्लीगी जमात की स्थापना मोहम्मद इल्यिास कांधलवी ने की थी। इस संगठन का नारा था 'मुसलमानों मुसलमान बनो'। इस संगठन का मुख्यालय आज भी दिल्ली की बस्ती निजामुद्दीन की मस्जिद बंगलेवाली में है। मौलाना इल्यिास का संबंध सुन्नी मुसलमानों के देवबंदी सम्प्रदाय से था जो कि वहाबी और सल्फी आदर्शों में विश्वास रखता है। इसके बाद मुसलमानों के विभिन्न संगठनों ने अपना सारा जोर आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन को रोकने और मुसलमानों में वहाबी और जिहादी विचारधारा के प्रचार पर लगा दिया। कोरोना महामारी के दौरान तब्लीगी जमात विश्व भर में चर्चा का विषय बना था। यह संगठन प्रचार की चमक-धमक से दूर इस्लाम का प्रचार करता है। इस समय इसका मकड़जाल विश्व के 111 देशों में फैला हुआ है और इसके अनुयायियों की संख्या 20 से 25 करोड़ के बीच बताई जाती है। अमेरिका की फेडरल एजेंसी के अनुसार यह आतंकवादी जिहादी संगठन है।

सीताराम गोयल ने अपनी पुस्तक 'मुस्लिम सेपरेटिज्म' में स्वामी श्रद्धानन्द जी की हत्या के लिए तब्लीगी जमात को दोषी ठहराया था। 'दक्षिणो एशिया में मुस्लिम कट्टरवाद' नामक पुस्तक के लेखक मुमताज अहमद ने यह मत व्यक्त किया है कि इस्लामी आतंकवाद को भड़काने में तब्लीगी जमात का प्रमुख हाथ रहा है। साहिल मायाराम ने अपनी पुस्तक 'रेजिस्टिंग रेजिम' में यह मत व्यक्त किया है कि तब्लीगी जमात की आतंकवादी पृष्ठभूमि सैयद अहमद बरेलवी के वहाबी आंदोलन और शरीयत उल्लाह के फिराजी आंदोलन से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भारत में तब्लीगी आंदोलन को विदेशी स्रोतों से भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त होती रही है। ■

तस्लीम रहमानी का पॉपुलर फ्रंट से त्यागपत्र

दिल्ली के विवादित मुस्लिम नेता डॉ. तस्लीम अहमद रहमानी ने पॉपुलर फ्रंट और उसके राजनीतिक विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से त्यागपत्र दे दिया है। इससे पूर्व उन्होंने पॉपुलर फ्रंट के उम्मीदवार के तौर पर केरल के मलप्पुरम लोकसभा उपचुनाव में भाग लिया था, जिसमें उनकी जमानत जब्त हो गई थी। डॉ. तस्लीम अहमद रहमानी ने 3 नवंबर को एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैजी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अन्य सभी पदों से त्यागपत्र देता हूं। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि मैं हालांकि पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से सहमत हूं मगर जिस तरह से उसे लागू किया जा रहा है उससे असहमत हूं। इसको एक राजनीतिक पार्टी के रूप में लागू किए जाने की बजाय एक कॉर्पोरेट पार्टी के रूप में लागू किया जा रहा है। मैंने अनेक बार पार्टी के हाईकमान से अनुरोध किया था कि एक राजनीतिक संस्कृति अपनाई जाए और इस संदर्भ में खुले तौर पर जनता के सामने अपना कार्यक्रम पेश किया जाए। मगर इस ओर पार्टी हाईकमान ने कोई ध्यान नहीं दिया। ना

ही मीडिया में अपने सिद्धांतों और विचारधारा का प्रचार किया है इसलिए पार्टी जनता को आकर्षित करने में पूरी तरह से विफल रही है। अत: मैंने इस पार्टी से चार वर्ष के बाद संबंध विच्छेद करने का फैसला किया है। चार वर्ष पूर्व डॉ. तस्लीम रहमानो ने अपनी पार्टी मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का पॉपुलर फ्रंट में विलय करने की घोषणा की थी। तस्लीम रहमानी नगर निगम, विधान सभा और लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं मगर वे चुनाव जीतने में आज तक सफल नहीं हो पाए हैं।

इंकलाब (10 नवंबर) के अनुसार तस्लीम रहमानी ने पार्टी नेतृत्व और उसकी रणनीति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। इंकलाब के प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीपीआई में लोकतंत्र का नामोनिशान नहीं है। पार्टी के फैसले कहां होते हैं यह किसी को पता नहीं और तथाकथित संघर्ष का कोई नामोनिशान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उस समय इस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया था जब यह पार्टी संकट में थी। मिल्लत के हित के कारण वे इसमें शामिल हुए थे। मगर आज पार्टी का नेतृत्व न सिर्फ भयभीत है बल्कि उसके पास किसी भी समस्या से निपटने की कोई रणनीति मौजूद नहीं है। पार्टी किसी भी समस्या पर सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने को ही काफी समझती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में काम करने नहीं दिया गया। बाबरी मस्जिद के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था उसे न्यायालय में पुनर्विचार के लिए पेश किया जा सकता था। मगर बार-बार अनुरोध करने के बावजूद पार्टी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए यह जरूरी है कि वे दलित व आदिवासी क्षेत्रों में निष्ठापूर्वक कार्य करें ताकि वे इन वर्गों के साथ एक संयुक्त मोर्चा बना सकें। आरएसएस का मुकाबला करने के लिए यह रणनीति अपनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास कोई रणनीति नहीं है। जहां तक मुस्लिम मजलिस का संबंध है वह सिर्फ चुनाव के समय ही मैदान में आती है।

अफगानिस्तान पर सुरक्षा सलाहकारों की बैठक

इंकलाब (11 नवंबर) के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में आठ देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। यह बैठक भारत की पहल पर बुलाई गई थी। इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान को कभी भी वश्विक आतंकवाद का गढ़ नहीं बनने दिया जाएगा। आतंकवाद, अतिवाद और आतंकवादियों की सीमा पर गतिविधियों को रोका जाएगा। इस बैठक में अफगानिस्तान में मादक पदार्थों की पैदावार, उनकी तस्करी और तालिबान के हाथों लगे अमेरिकी अस्त्र-शस्त्रों के विशाल भंडारों के कारण उत्पन्न हुई चुनौती पर भी विचार किया गया। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान में जो स्थिति बनी है उससे निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति तैयार की जानी चाहिए। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान के नागरिकों के सभी वर्गों का बिना किसी भेदभाव के मानवीय आधार पर सहायता उपलब्ध करवाई जाए। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने की। जबकि इस बैठक में ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सुरक्षा परिषद के सचिवों ने भाग लिया। भारत के पहल पर आयोजित होने वाली इस बैठक में पाकिस्तान और चीन को भी निमंत्रण दिया गया था मगर उन्होंने इसमें भाग लेने से इंकार कर दिया। इन आठ देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान के लिए अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय सुरक्षा का सम्मान करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने का भी आश्वासन देते हुए अफगानिस्तान में जनता पर होने वाली कठिनाईयों पर गहरी चिंता प्रकट की है।

बैठक में अफगानिस्तान में विभिन्न स्थानों पर हुए आतंकवादी हमलों की निंदा करने के साथ-साथ उनमें मारे जाने वाले लोगों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की गई। इस बैठक में यह स्वीकार

किया गया कि अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं का न केवल अफगानिस्तान के नागरिकों पर बल्कि पड़ोसी और आसपास के देशों पर भी गंभीर असर पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अजीत डोवाल ने कहा कि हम सब आज अफगानिस्तान से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने के लिए इक्ठ्ठे हुए हैं। आज इस बात की जरूरत है कि हम अफगानिस्तान की समस्याओं के समाधान के लिए आपस में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और एकजुट हों। भारत के लिए यह गौरव की बात है कि उसे मध्य एशियाई देशों और रूस के साथ वार्ता करने का अवसर मिल रहा है। हम सब अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं पर गहरी नजर रखे हए हैं। क्योंकि वहां पर होने वाली घटनाएं इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमारी वार्ता सफल होगी।

कजाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष करीम मासोमोव ने कहा कि अफगानिस्तान में बढ़ते हुए आर्थिक और मानवीय संकट ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। वहां पर दिन-प्रतिदिन सामाजिक और आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हमें अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भारी चिंता है। इसलिए यह जरूरी है कि अफगानिस्तान को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की जाए। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शामखानी ने अफगानिस्तान से होने वाले पलायन की संभावनाओं पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि इसको रोकने का एक ही समाधान है कि वहां पर एक व्यापक सरकार का गठन हो, जिसमें सभी कबीलों और नस्लों के लोगों को शामिल किया जाए। पड़ोसी होने के नाते हम अफगान जनता की सहायता के लिए तैयार हैं। ताजिकिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव नसरुलो महमूदजोदा ने कहा कि क्योंकि ताजिकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है इसलिए वहां क घटनाक्रम का हम पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अफगानिस्तान के कारण हमारे देश में आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए हम सीमा पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। किर्गिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठनों के कारण इस सारे क्षेत्र में बहुत विकट स्थिति पैदा हो रही है। इसका हमें मिलकर ही समाधान करना चाहिए।

रोजनामा सहारा (12 नवंबर) ने अपने संपादकीय में भारत द्वारा अफगानिस्तान के बारे में आयोजित सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का स्वागत किया है और कहा है कि अमेरिकी सैनिकों के पलायन और निर्वाचित अशरफ गनी के वहां से फरार होने और अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत की चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र के एक महत्त्वपूर्ण देश होने के कारण भारत ने अफगानिस्तान क नवनिर्माण और स्थिरता में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं है कि अफगानिस्तान के मामले में भारत अलग-थलग रहे और वहां पर होने वाले घटनाक्रम को नजरअंदाज करे। यही कारण है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस मामल में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है और इस क्षेत्र के देशों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मध्य एशिया के पांच देशों के अतिरिक्त ईरान और रूस ने भी भाग लिया है।

इस बैठक के समापन के बाद जो संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया है उसमें बारह सूत्री कार्यक्रम में अफगानिस्तान के नवनिर्माण और विकास के हवाले से कई बातें कही गई हैं। घोषणापत्र मं अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति, आतंकवादी घटनाओं और उससे पैदा होने वाल खतरों के निराकरण के लिए ठोस कदम उठाने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मानवीय सहायता को हर कीमत पर जारी रखा जाए। घोषणापत्र में यह इच्छा

व्यक्त की गई है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो और राजनीतिक स्थिरता आए। इसके साथ ही अफगानिस्तान को यह भी आश्वासन दिया गया है कि उसकी सार्वभौमिकता का सम्मान किया जाएगा और उसके आंतरिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल आतंकवाद का प्रोत्साहन देने, आतंकवादियों के प्रशिक्षण और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में एक व्यापक सरकार बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया जिसे अफगानिस्तान की जनता के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो।

हालांकि इस बैठक में चीन और पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। मगर उसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने अपना एक समानांतर अधिवेशन बुला लिया, जिसमें रूस, अमेरिका और चीन को बुलाकर पाकिस्तान ने भारत द्वारा किए गए प्रयासों को हल्का करने का प्रयास किया मगर उसे इस प्रयास में सफलता नहीं मिली। क्योंकि तालिबान ने भारत द्वारा पहल का स्वागत किया ह और उसे अफगानिस्तान के हित में बहुत बड़ा कदम करार दिया है और यह आशा व्यक्त की है कि इससे अफगानिस्तान में शांति आर स्थिरता लाने में सहायता मिलेगी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से तालिबान का रूख भारत के प्रति उदार रहा है और तालिबान ने भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। यहां तक कि कश्मीर के मामले पर भी उन्होंने अपना दामन बचाने का प्रयास किया है। तालिबान यह कह चुके हैं कि यह भारत का अंदरूनी मामला है और वे इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। दिल्ली समझौते का तालिबान की ओर से स्वागत इसी बात का संकेत है कि वह भारत के साथ टकराव नहीं चाहता। तालिबान इस बात को समझते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का पूंजी निवेश कर रखा है। अफगानिस्तान के नवनिर्माण के विभिन्न कार्यक्रमों में भारत ने तीन अरब अमेरिकी डॉलर की पूंजी लगा रखी है। इसलिए अभी अफगानिस्तान को भारत की सख्त जरूरत है। तालिबान ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अफगानिस्तान में नवनिर्माण की योजनाओं को जारी रखे।

इत्तेमाद (11 नवंबर) ने अपने संपादकीय में भारत द्वारा अफगानिस्तान पर बुलाई गए सम्मेलन पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा है कि इसमें अफगानिस्तान का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था और न ही इसमें पाकिस्तान और चीन ने ही भाग लिया। इसमें सिर्फ रूस और उसके पुराने राज्यों के प्रतिनिधि ही शामिल हुए। जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान ने जो सम्मेलन बुलाया था उसमें तालिबान का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का संबंध है अफगानिस्तान मे होने वाले नए बदलाव और वहां के नेताओं द्वारा कश्मीर का हवाला दिए जान से भारत फिक्रमंद है। हालांकि यह पहला मौका है जब भारत द्वारा बुलाई गई बैठक में मध्य एशिया के सभी मुस्लिम देश शामिल हो रहे हैं।

पाकिस्तान ने यह घोषणा की थी कि क्योंकि भारत द्वारा आयोजित बैठक में तालिबान भाग नहीं ले रहे हैं इसलिए वह भी इसमें हिस्सा नहीं लेगा। खास बात यह है कि पाकिस्तान द्वारा बुलाई गई बैठक में तालिबान के विदेश मंत्री तक ने भाग लिया। हालांकि सवाल यह है कि क्या तालिबान सिर्फ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के सहारे ही अपने देश में स्थिरता ला सकते हैं? अभी तक पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी ह। भारत की इच्छा है कि तालिबान की सरकार इस बात की गारंटी दे कि वह अपने देश की भूमि को किसी भी अन्य देश में आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा।

वक्फ भूमि घोटाले में नवाब मलिक घेरे में

मुंबई उर्दू न्यूज (12 नवंबर) के अनुसार पिछले कुछ दिनों से भाजपा और समीर वानखेडे को निशाना बनाने वाले नवाब मलिक अब मुश्किलों में उलझते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ने औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड की भूमि के घोटाले की जांच शुरू कर दी है और इस संदर्भ में सात स्थानों पर छापे मारे गए हैं। नवाब मलिक ने इन छापों पर टिप्पणो करते हुए कहा कि मैं पूछताछ से नहीं डरता। मगर बीजेपी के जिन नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की थी उनका क्या हुआ? ये छापे वक्फ बोर्ड की ओर से भूमि घोटाले के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। इससे पहले पुणे में सात स्थानों पर छापे मारे जा चुके हं। पुणे की बंद गार्डन पुलिस के अनुसार अगस्त महीने में गिरफ्तार होने वालों में ट्रस्ट बोर्ड के कुछ ट्रस्टी भी थे मगर अब इस बात का पता चला है कि बोर्ड के कुछ अन्य अधिकारियों ने भी बोर्ड की संपत्तियों का अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। ताजा जानकारी के अनुसार औरंगाबाद में कई जगह पर छापे मारे गए। इनमें दो प्रमुख उद्योगपति भी शामिल हैं।

नवाब मलिक ने पत्रकार सम्मेलन में दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर कोई छापा नहीं मारा है। जो कार्रवाई की जा रही है वह पुणे क एक ट्रस्ट की है। नवाब मलिक के मुताबिक इस ट्रस्ट को चैरिटी कमीशन ने 2009 में वक्फ बोर्ड को स्थानांतरण किया था। 1995 में जब महाराष्ट्र में डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनी तो वक्फ एक्ट लागू किया गया। इसके बाद चैरिटी कमीशन ने इन ट्रस्टों के डीड को रजिस्टर करने का फसला किया जो चैरिटी कमीशन में रजिस्टर थे। नवाब मलिक ने दावा किया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का पद संभालने के बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड के दस सदस्यों को मनोनीत किया। अगर हमारे पास कोई शिकायत आती तो हम जांच करते। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय है। वक्फ बोर्ड ने पिछले वर्ष सात मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें पुणे का यह ट्रस्ट भी शामिल है। इस

सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कुछ उच्चाधिकारी भी शामिल हैं। मैंने विभाग संभालने के बाद उसमें सफाई का अभियान चलाया था। मुझे प्रसन्नता है कि प्रवर्तन निदेशालय हमारे अभियान का समर्थन कर रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय उनके घर पर पहुंची है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ से नहीं डरता। हम संपूर्ण रूप से उसका सहयोग करेंगे। जो लोग यह समझते हैं कि वे ऐसी खबरों को फैलाकर नवाब मलिक को परेशान कर लेंगे वे गलतफहमी में हैं। अगर वक्फ बोर्ड की ठीक तरह से जांच होती है तो भाजपा के काफी लोग अंदर जाएंगे। कुछ लोग हरियाणा गए हैं वे और मुंबई के कुछ लोग भी मुश्किल में पड जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के जिन नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमे दर्ज किए हैं उनकी प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मुकदमे दर्ज किए थे वे जब भाजपा में शामिल हो गए तो उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई बंद कर दी गई। हम यह जरूर पूछेंगे कि यह कार्रवाई क्यों रोकी गई है? राजनीतिक दृष्टि से क्यों जांच की जा रही है? नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि भाजपा के कई नेताओं के मादक पदार्थ के तस्करों के साथ संबंध हैं। मलिक ने अमृता फडणवीस के साथ जयदीप राणा की एक फोटो भी ट्विट की थी और यह दावा किया था कि यह तस्कर है। दूसरी ओर

अमृता फडणवीस ने इस आरोप को गलत बताया है और कहा है कि अगर नवाब मलिक इस आरोप को वापस नहीं लेते हैं और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

सहाफत (12 नवंबर) के अनुसार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की बेटी निलोफर मलिक खान ने भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मानहानि और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में कानूनी नोटिस भेजकर पांच करोड़ हर्जाने की मांग की है। नोटिस में कहा गया है कि फडणवीस ने समीर खान पर मादक पदार्थ रखने का आरोप लगाया है। जबकि अभी तक मामले की जांच जारी है और नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें कोई ऐसा आरोप शामिल नहीं है। नोटिस में कहा गया है कि 14 जनवरी 2021 को जब नार्कोटिक्स बोर्ड ने उनके मकान की तलाशी ली थी तो उन्हें लिखित रूप से यह सूचित किया गया था कि उनके मकान से कोई भी मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। इसके बावजूद उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर फडणवीस ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगे और 48 घंटे के अंदर सभी झूठे ट्विट डिलीट नहीं किए तो हम न्यायालय में जाएंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (10 नवंबर) के अनुसार पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक ने नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे के खिलाफ जो आरोप लगाए थे उसी सिलसिले में भाजपा को निशाना बनाया गया तो भाजपा ने जवाब में नवाब मलिक पर भी धावा बोल दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया है और इस संबंध में कुछ दस्तावेज भी पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक ने 1993 में मुंबई धमाकों में उम्रकैद की सजा पाने वाले आरोपी शाह वली खान के साथ मिलकर जमीन खरीदी थी। एलबीएस रोड मुंबई पर पौने तीन एकड़ भूमि की पावर ऑफ अटॉर्नी शाह वली खान और सलीम पटेल के पास थी। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि साढ़े तीन करोड़ की भूमि जिस कंपनी ने खरीदी थी उससे नवाब मलिक के रिश्ते थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस भूमि कांड में सलीम पटेल का नाम शामिल है जो दाउद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर था। साढ़े तीन करोड़ की इस भूमि को नवाब मलिक ने सिर्फ 22 लाख रुपये में खरीदा था। उन्होंने कहा कि पांच लेनदेन में नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते पाए गए हैं। मैं इन सभी दस्तावेजों को संबंधित जांच एजेंसियों और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजूंगा ताकि उन्हें मालूम हो सके कि उनके मंत्री क्या कर रहे है।

हमारा समाज ने 12 नवंबर के संपादकीय में कहा है कि जब कोई चोर किसी मामले में फंसता है तो उसके पुराने कारनामे भी सामने आ जात हैं और उसके आरोपों का पुलिंदा खुल जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी समीर वानखेडे के बारे में भी लोगों की ऐसी ही राय है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब वानखेडे को अपना पीछा छुड़ाना भारी पड़ रहा है। यहां तक कि अब भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री को भी इस विवाद मं शामिल होना पड़ा है। वे आरोपों का जवाब देने की बजाय नवाब मलिक को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मगर नवाब मलिक भी हार मानने वाले नहीं लगते वे आरोपों का पूरा पुलिंदा लिए हुए हैं। हो सकता है कि उनके आरोप सत्य पर आधारित हों। आज सभी लोगों की नजरें मुंबई में विभिन्न नेताओं के बीच चल रहे वाकयुद्ध पर लगी हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि इन गंभीर आरोपों के बावजूद केंद सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। नवाब मलिक ने फडणवीस के खिलाफ यह आरोप लगाया है कि वे जाली करेंसी और फर्जी वसूल को प्रोत्साहन देने के जिम्मेवार हैं। इसलिए यह जरूरी है कि फडणवोस अपने आप को पाक-साफ साबित करने के लिए स्वयं को निर्दोष साबित करें। भाजपा को भी अपनी सफाई देनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नवाब मलिक के आरोप समीर वानखेड पर बेबुनियाद हों और फिर भी वे प्रेस कांफ्रेंस कर के झूठ बोल रहे हैं।

विश्व

इमरान सरकार ने अतिवादी इस्लामिक संगठन के सामने घुटने टेके

इंकलाब (1 नवंबर) के अनुसार इमरान सरकार और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के बीच गत तीन वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था अब उसने नया मोड़ लिया है। इमरान सरकार को इस अतिवादी संगठन के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, राष्ट्रीय असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर और टीएलपी के नेता मुफ्ती गुलाम अब्बास फैजी ने एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते की घोषणा की। उन्होंने यह दावा किया कि इस समझौते की पुष्टि टीएलपी के प्रमुख साद हुसैन रिजवी ने भी की है। यह समझौता किसी भी पार्टी की जीत या हार नहीं है बल्कि यह पाकिस्तान और इस्लाम की जीत है। इससे पाकिस्तान में शांति और स्थिरता को प्रोत्साहन मिलेगा। इस समझौते को लागू करने के लिए एक कमेटी अली मोहम्मद खान की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें पाकिस्तान सरकार के उच्चाधिकारी और टीएलपी के नेता शामिल हैं।

हमारा समाज (3 नवंबर) के अनुसार तहरीक-ए-लब्बैक और पाकिस्तान सरकार के बीच समझौता तो हो गया है मगर अभी तक दोनों पक्षों में अविश्वास का वातावरण बना हुआ है। टीएलपी ने अभी तक यह घोषणा नहीं की कि इस्लामाबाद को घेरने के लिए लॉन्ग मार्च के कार्यक्रम को रद्द किया जा रहा है और न ही सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जीटी रोड़ पर अनेक स्थानों पर की गई रूकावटों को ही हटाया है। इस समझौते की घोषणा के बाद यह जरूर हुआ है कि विभिन्न स्थानों पर सेना ने सड़क पर जिन कंटेनरों को खड़ा किया हुआ था उन्हें सड़क पर से हटाकर बगल में खड़ा कर दिया गया है। मगर गुजरात में दरिया चिनाब के तीनों पुलों पर नाकाबंदी को और भी सख्त किया गया है। बिना पहचानपत्र दिखाए किसी भी व्यक्ति को पुलों पर

से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। वजीराबाद के पास टीएलपी के जो कार्यकर्ता हजारों की संख्या में शामिल हुए थे अभी तक वे वहीं डेरे डाले हुए हैं। हालांकि टीएलपी के नेता मुफ्ती अमीर ने यह दावा किया है कि 5000 के करीब उनके जिन कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान सरकार ने गिरफ्तार कर रखा है उन्हें शीघ्र ही रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने यह फैसला किया है कि फ्रांसोसी राजदूत की वापसी और फ्रांसीसी दूतावास को बंद करने की मांग पर जोर न दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के प्रमुख को जेल से शीघ्र रिहा किए जाने की भी संभावना है। हालांकि इस संगठन पर पाकिस्तान सरकार ने जो पाबंदी लगा रखी है उसे नहीं हटाया गया परंतु उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि इस पार्टी पर अप्रैल महीने में पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका ने इस समझौते पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है और कहा है कि उनकी नजर में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एक आतंकवादी संगठन है।

औरंगाबाद टाइम्स (4 नवंबर) के अनुसार प्रतिबंधित संगठन टीएलपी ने यह आश्वासन दिया है कि वे हिंसक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। इसके बदले में उन्होंने मांग की है उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (28 अक्टूबर) के अनुसार टीएलपी के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए सरकार ने गुजरांवाला के समीप सड़क पर 30-30 फुट की गहरी खाईयां खोद दी हैं और पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बस और रेल सेवा को भी बंद कर दिया गया है। इससे पूर्व इस्लामाबाद और रावलपिंडी को अर्द्धसैनिक दस्तों ने चारों तरफ से घेर लिया था।

टिप्पणी : तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (मैं हूं वर्तमान पाकिस्तान) नामक एक कट्टर इस्लामिक राजनीतिक संगठन है जिसकी नींव खादिम हुसैन रिजवी ने अगस्त 2015 में रखी थी। हालांकि राष्ट्रीय असेंबली आर पंजाब असेंबली में यह पार्टी चुनाव में कोई जीत हासिल नहीं कर सकी है। मगर वह पाकिस्तान की पांचवी सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभरी है। सिंध असेंबली में उसे तीन सीटें जरूर प्राप्त हुई हैं। इस पार्टी के अधिकांश नेता और कैडर बरेलवी संप्रदाय की कट्टर विचारधारा क पोषक है। इनकी मांग है कि पाकिस्तान में शरिया को लागू किया जाए आर ईशनिंदा, रसूल और कुरान की निंदा करने वाले को सार्वजनिक रूप से फांसी देने का कानून बनाया जाए। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्रेन है। 23 नवंबर 2018 को पाकिस्तान मंत्रिमंडल के निर्देश पर पाकिस्तान के अर्द्धसैनिक दस्तों ने इसके प्रमुख खादिम हुसैन रिजवी को कई सौ कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार ने इस संगठन से संबंधित कोई भी समाचार प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। खादिम हुसैन रिजवी, पीर अफजल कादरी और इनायत हक शाह, फारूको हसन आदि नेताओं पर देशद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए थे। फ्रांस में पैगम्बर मोहम्मद के कार्टून प्रकाशित किए जाने के बाद इस संगठन ने यह मांग की थी कि पाकिस्तान में फ्रांस के दूतावास को बंद किया जाए और सरकार यूरोपीय यूनियन के साथ संबंध विच्छेद कर ले। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। पुलिस और इस संगठन के समर्थकों में हुई झड़पों में एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान क अनेक भागों में हिंसा भड़क उठी थी। सरकारी संपत्तियों को आग लगा दी गई थी। यह संगठन तब ज्यादा चर्चा में आया था जब आसिया बीबी नामक एक ईसाई महिला को कुरान का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे न्यायालय से रिहा कर दिया गया था। इस संगठन की मांग थी कि

आसिया बीबी और उसे रिहा करने वाले उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को मौत की सजा दी जाए और उनके सिर सार्वजनिक रूप से तलवार से काट दिए जाएं। आसिया बीबी को पाकिस्तान के ईशनिंदा कानून के अनुसार फांसी की सजा दी गई थी, जिसे बाद में उम्रकैद में बदला गया था। जब इसके खिलाफ दुनिया भर में पाकिस्तान की निंदा हुई तो पाकिस्तान सरकार ने नवंबर 2018 में आसिया बीबी को मुल्तान जेल से रिहा करके उसे गुप्त रूप से यूरोपीय देश नीदरलैंड भिजवा दिया गया था। इस घटना के खिलाफ टीएलपी ने देशव्यापो उग्र प्रदर्शन किए थे। टीएलपी को भारत के बरेलवी संप्रदाय का खुला समर्थन प्राप्त है।

अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के 600 आतंकी गिरफ्तार

औरंगाबाद टाइम्स (12 नवंबर) के अनुसार अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद तालिबान अब तक इस्लामिक स्टेट के 600 से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार कर चुके हैं जो कि आईएसआईएस खुरासान नामक संगठन के हैं। अफगानिस्तान के गुप्तचर विभाग के एक प्रवक्ता ने यह दावा किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में इस्लामिक स्टेट के कुछ कमांडर भी शामिल हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इन लोगों को गिरफ्तार करके गुप्त जेलों में रखा गया है। अब तक तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच हुए झड़पों में 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने यह दावा किया कि अफगानिस्तान की पुरानी सरकार ने इस्लामिक स्टेट से संबंधित 2000 से अधिक लोगों को जेलों से रिहा कर दिया था। उन्होंने कहा कि यही लोग अब अफगानिस्तान में विभिन्न जगहों पर बमों के धमाके करके तबाही मचा रहे हैं। कंधार और काबुल में मस्जिदों में हुए एक दर्जन धमाकों के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है, जिनमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता थॉमस वेस्ट ने यह दावा किया कि दक्षिण एशियाई देशों में इस्लामिक स्टट और अलकायदा बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रह हैं और यह विश्व शांति के लिए खतरा है।

सियासत (3 नवंबर) के अनुसार पुरानी अफगान सरकार के सैकड़ों अधिकारी तालिबान से भयभीत होकर इस्लामिक स्टेट का दामन थाम चुके हैं। क्योंकि उन्हें यह भय है कि अगर वे तालिबान के कब्जे में आ गए तो वे उनकी हत्या कर देंगे। ये लोग अपने साथ भारी मात्रा में पुरानी अफगान फौज के हथियारों और गोला बारूद ले गए हैं। हाल ही में इन तत्वों ने एक नया आतंकवादी संगठन 'सहाब अल मुहाजिर' बनाया है। इस संगठन की बागडोर एक अज्ञात अरब के हाथ में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अफगानिस्तान में 2000-5000 तक सशस्त्र लोग इस्लामिक स्टेट के हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं और अशांति पैदा कर रहे हैं।

काबुल अस्पताल में धमाके में 20 मरे

इत्तेमाद (3 नवंबर) के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए दो धमाकों में कम-से-कम 20 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता कारी सईद खोस्ती ने इन धमाकों की पुष्टि की है और कहा है कि इन धमाकों के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ है जो अमेरिका के इशारे पर अफगानिस्तान में अशांति फैला रहे हैं।

इंकलाब (13 नवंबर) के अनुसार काबुल में हुए एक अन्य धमाके में कम-से-कम दस लोग मारे गए हैं।

सहाफत (12 नवंबर) के अनुसार अफगानिस्तान के नगर मजार-ए-शरीफ में चार महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन महिलाओं का संबंध मानवाधिकार रक्षक गुटों से बताया जाता है। इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान के गृहमंत्रालय के प्रवक्ता कारी सैयद खोस्ती ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार इन महिलाओं को दावत के नाम पर बुलाया गया था और बाद में उनको गोली मार दी गई। मीडिया समाचारों के अनुसार ये चारों महिलाएं अफगानिस्तान से भागकर विदेश जाना चाहती थीं। जब इस संबंध में तालिबान को जानकारी मिली तो उन्होंने इन चारों की हत्या कर दी।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 नवंबर) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने देश में विदेशी करेंसी के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब भविष्य में सभी लेन-देन अफगान करेंसी में ही हो सकेगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हितों को सामने रखते हुए यह फैसला किया गया है। क्योंकि इस समय देश के कई भागों में अमेरिकी और पाकिस्तानी करेंसी का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको रोकना बेहद जरूरी है।

बलूचिस्तान में पृथकतावादी सक्रिय

इंकलाब (10 नवंबर) के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान में बलोच लिब्रेशन आर्मी की गतिविधियों में तेजी आई है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार गत एक महीने में बलूचिस्तान में बलोच लिब्रेशन आर्मी और इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के आत्मघाती दस्तों ने पाकिस्तानी सेना और अद्धसैनिक संगठनों की चौकियों पर हमले किए जिनमें एक दर्जन से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान सरकार के अनुसार पृथकतावादी बलोच संगठनों के दो दर्जन विद्रोही भी पाकिस्तानी सैनिकों की गोलियों का शिकार बने हैं।

हमारा समाज (12 नवंबर) के अनुसार बलूचिस्तान विश्वविद्यालय के हॉस्टल से दो छात्र नेताओं का जबरन अपहरण कर लिया गया है। कहा जाता है कि इन छात्र नेताओं का अपहरण पाकिस्तानी गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों ने किया है। इस अपहरण के खिलाफ छात्र संगठन विश्वविद्यालय में धरना दे रहे हैं और उन्होंने परीक्षाओं का बहिष्कार भी कर दिया है। बलूचिस्तान विश्वविद्यालय के छात्र संगठन बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन (बीएसओ) के प्रवक्ता बलाच कादिर ने संवाददाताओं को बताया कि जिन छात्रों का अपहरण किया गया है उनके नाम फजीउल्लाह आर सुहैल अहमद हैं। इन दोनों का संबंध बलूचिस्तान के जिला नुश्की से है। छात्रों ने यह मांग की थी कि इन छात्रों का अपहरण करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को छात्रों के हवाले किया जाए। मगर पुलिस के दबाव के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन इन वीडियो फुटेज को देने से इंकार कर रहा है।

इन दोनों छात्रों के गुम हो जाने की रिपोर्ट उनके भाई ने पुलिस में दर्ज करवाई है। वॉयस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के अध्यक्ष नसरुल्लाह बलोच के नेतृत्व में क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर उग्र प्रदर्शन किया गया, जिसमें इस बात की मांग की गई कि पाकिस्तान के एजेंसियों द्वारा बलूचों को जिस तरह से जबरन अपहरण किया जा रहा है उस सिलसिले को रोका जाए और अपहरण किए गए लोगों को रिहा किया जाए। वॉयस ऑफ अमेरिका के प्रधिनिधि से बातचीत करते हुए नसरुल्लाह बलोच ने दावा किया कि पाकिस्तान सरकार का विरोध करने के कारण पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियां गैरकानूनी रूप से ऐसे लोगों का अपहरण कर रही हैं। पिछले दो सप्ताह में ऐसे 16 लोगों का अपहरण किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का जबरन अपहरण किया जाता है उनकी लाशें बाद में विभिन्न स्थानों पर पड़ी मिलती हैं और उनका अपहरण करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्योंकि वे सरकारी विभागों से जुड़े हुए होते हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने आजाद बलूचिस्तान के समर्थकों के लापता होने की घटनाओं की निंदा की है और प्रधानमंत्री इमरान खान से अपील की है कि वे ऐसी गैरकानूनी हरकतों को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करें।

म्यांमार में इस्लामिक आतंकियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की तैयारी

सहाफत (12 नवंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने म्यांमार में हिंसा की संभावनाओं पर चिंता प्रकट करते हुए वहां की सरकार से अपील की है कि वह हिंसा को रोकने के लिए कार्रवाई करे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह बयान उस समय जारी किया है जब म्यांमार के रखाइन क्षेत्र में सेना और रोहिंग्या इस्लामिक मिलिशिया के बीच व्यापक हिंसा के समाचार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रकाशित हुए हैं। इन समाचारों के अनुसार म्यांमार सरकार ने भारी संख्या में सेना को मुस्लिम बहुल क्षेत्र रखाइन में भेजा है जहां पर इस्लामिक आतंकवादी सशस्त्र कार्रवाई कर रहे हैं। विद्रोही संगठनों के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि कुछ वर्ष पूर्व सेना और विद्रोही संगठनों के बीच जो युद्ध विराम हुआ था वह समाप्त हो गया है और इस पूरे क्षेत्र में सेना और विद्रोहियों के बीच सशस्त्र संघर्ष तेज हो गया है।

उन्होंने कहा कि म्यांमार के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए अराकान आर्मी नामक संगठन को पुनः अपने लोगों की रक्षा के लिए हथियार उठाने पड़े हैं। क्योंकि म्यांमार की सेना भारी अस्त्र-शस्त्रों के साथ टैंकों में सवार होकर उनके क्षेत्र में दाखिल हो गई हैं और व निहत्थी जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। नागरिकों की हत्या के साथ-साथ उनकी संपत्ति और गांव को जलाया जा रहा है और महिलाओं के साथ सामुहिक बलात्कार किया जा रहा है। एक दशक पूर्व भी म्यांमार की सेना ने इस क्षेत्र में जो सैनिक कार्रवाई की थी उसके कारण 40 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को जान बचाने के लिए बांग्लादेश और अन्य देशों में शरण लेनी पड़ी थी। अब भी म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर 20 लाख रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में डेरे डाले हुए हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से इन रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश सरकार ने बंगाल की खाड़ी के कुछ द्वीपों पर पुनर्वास का जो प्रयास किया था वह फिलहाल सफल नहीं हो रहा है। क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थी वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं।

इराक के प्रधानमंत्री की हत्या करने का प्रयास

हमारा समाज (8 नवंबर) के अनुसार इराक के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह घोषणा की है कि इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-कादिमी की ड्रोन द्वारा हत्या करने का जो प्रयास किया गया था वह विफल हो गया है। प्रधानमंत्री इस हमले में बच गए हैं। यह हमला उनके आवास पर किया गया था। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि चालक रहित ड्रोन द्वारा प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख की हत्या करने की कोशिश की गई थी जो कि विफल हो गई। इस साजिश का पता लगाने का प्रयास सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं।

अल अरेबिया के पत्रकार के अनुसार इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-कादिमी के निवास स्थान को मिसाइल से निशाना बनाया गया था। यह मिसाइल उनके घर पर गिरा और इस हमले मे पांच लोग घायल हो गए परंतु प्रधानमंत्री सुरक्षित रहे। एक अन्य ड्रोन को सैनिकों ने मार गिराया।

इत्तेमाद (10 नवंबर) के अनुसार इराकी प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर हमला करने की साजिश रचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों का संबंध शिया आतंकवादी ग्रुप से है। उन्हें जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। इराक सरकार के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि इराकी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश ईरान में तैयार की गई थी और इस हमले में ईरान में बने ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इराकी प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तीन ड्रोन भेजे गए थे, जिनमें से दो रास्ते में ही सैनिकों ने मार गिराए थे। मगर तीसरा प्रधानमंत्री के निवास स्थान को निशाना बनाने में सफल रहा। इस हमले में इमारत को क्षति पहुंची है और प्रधानमंत्री के रक्षक जख्मी हुए हैं।

इस घटना के बाद ईरान और इराक के बीच तनाव बढ़ गया है। बगदाद की सड़कों पर सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई है और जगह-जगह सैनिक तैनात किए गए हैं। इराकी सरकार का दावा है कि हाल के चुनाव में क्योंकि ईरान के समर्थकों की करारी हार हुई है इसलिए

व अब हिंसा का सहारा ले रहे हैं। ईरानो मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब ने हाल ही में इराक का दौरा किया था और उनके इशारे पर इस हमले की साजिश रची गई है। इस हमले के पीछे 'कताइब हिजबुल्लाह' और 'असाइब अल हक' का हाथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने इराकी प्रधानमंत्री पर हुए हमले की निंदा की है और मांग की है कि इस हमले के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सूत्रों का कहना है कि इस हमले में जो ड्रोन और विस्फोटक पदार्थ इस्तमाल किए गए हैं वह ईरान के बने हुए हैं।

इत्तेमाद (6 नवंबर) के अनुसार बगदाद में हाल ही में हुए चुनाव में हुई धांधलियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों और सैनिकों के बीच हुई झड़पों में कम-से-कम 100 से अधिक लोग जख्मी हो गए। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि जानबूझकर ईरान समर्थकों को इन चुनावों में हराया गया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सैनिकों द्वारा चलाई गई गोली में कई प्रदर्शनकारी भी मारे गए हैं। मगर सरकारी प्रवक्ता ने इन खबरों का खंडन किया है।

इत्तेमाद (11 नवंबर) के अनुसार अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि इराकी प्रधानमंत्री पर हुए हमले में ईरान के समर्थक ग्रुपों का हाथ है। प्रवक्ता ने कहा कि यह हमला इराक की स्वायत्तता और स्थिरता पर हमला है। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने इस हमले की निंदा को है और कहा है कि सऊदी सरकार पूरी तरह से इराक के साथ है। उन्होंने मांग की है कि इस हमले के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

इथियोपिया में विद्रोह

इत्तेमाद (7 अक्टूबर) के अनुसार इथियोपिया में तिग्रे विद्रोही देश की राजधानी अदीस अबाबा के समीप पहुंच गए हैं। विद्रोहियों का दावा है कि सरकारी सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जबकि सरकार ने पूरे देश में छह महीने के लिए आपातकाल लगा दिया है और यह दावा किया है कि स्थिति उनके नियंत्रण में है। जबकि विद्रोहियों का कहना है कि 1200 से अधिक सरकारी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है। मीडिया के अनुसार राजधानी अदीस अबाबा में स्थिति सामान्य है। आपातकाल की घोषणा के बाद देश के प्रधानमंत्री को विशेष अधिकार प्राप्त हो गए हैं, जिसके तहत वे देश के 18 वर्ष से अधिक आय् के किसी भी नागरिक को जबरन सेना में भर्ती कर सकते हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत इथियोपिया छोड़ने का निर्देश दिया है। जबकि अन्य देशों के दूतावास और नागरिक भी भारी संख्या में इथियोपिया से भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने सरकार और विद्रोहियों से तुरंत हिंसा बंद करने की अपील की है। इस अपील पर सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इथियोपिया में गत कई महीनों से गृहयुद्ध चल रहा है मगर हाल ही में उसमें तेजी आई है। विद्रोहियों ने अनेक नगरों पर कब्जा कर लिया है। इजरायली सरकार ने अपने नागरिकों को कहा है कि वे इथियोपिया न जाएं और जो वहां पर रह रहे हैं वे वापस आ जाएं।

अवधनामा (7 नवंबर) के अनुसार इथियोपिया के नौ विपक्षी दलों ने यह मांग की है कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की सरकार को बर्खास्त किया जाए ताकि देश में गृहयुद्ध को रोका जा सके। इन विपक्षी दलों ने यह भी दावा किया है कि गृहयुद्ध के कारण लाखों लोग देश से पलायन कर रहे हैं और देश में अकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं और लोगों के पास खाने पीने के सामान का बहुत अभाव है। इन दलों ने

संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग की है कि वह भुखमरी को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करे। इथियोपिया में 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले अबी अहमद ने टीपीएलएफ के विद्रोह को समाप्त करने के लिए गत वर्ष नवंबर महीने में सैनिक दस्ते भेजे थे। इसके बाद उत्तरी इथियोपिया में गृहयुद्ध चल रहा है और सरकारी सेना तथा टीपीएलएफ के सैनिकों में सशस्त्र संघर्ष जारी है और यह युद्ध देश के कई भागों में फैल गया है।

अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को अस्त्र–शस्त्रों की सप्लाई

इत्तेमाद (5 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका ने 65 करोड़ डॉलर के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की बिक्री सऊदी अरब को करने का फैसला किया है। इससे साफ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद अरब देशों को भविष्य में अस्त्र-शस्त्र सप्लाई न करने की जो घोषणा की थी उसमें अब बदलाव किया है। सऊदी अरब को 650 मिलियन डॉलर के एफ-15 युद्ध विमानों के साथ-साथ मिसाइल और गोला बारूद बेचने का भी फैसला किया गया है। अमेरिका ने सऊदी अरब को 280 एआईएम-120 नामक मिसाइल बेचने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त 596 एलएयू-128 मिसाइल भी बेचे जाएंगे। इनका इस्तेमाल सऊदी अरब के सैनिक विमानों में किया जा सकेगा।

अमेरिका के विदेश मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि सऊदी अरब की रक्षा करना

अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। इससे पूर्व ट्रम्प प्रशासन की ओर से सऊदी अरब को अस्त्र-शस्त्र बेचने की जो नीति अपनाई जा रही थी उस पर बाइडेन ने सत्ता में आते ही प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता है कि ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने यह फैसला किया है। अमेरिका के इस फैसले से सऊदी सरकार को यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

इजरायल ईरान के साथ युद्ध के लिए तैयार

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इजरायल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के सहयोग से एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास तेज कर दिया है। ईरान पर दबाव डालने के लिए हाल ही में इन देशों ने ईरान के समीप समुद्र में युद्धाभ्यास किए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 नवंबर) के अनुसार इजरायल के सेना प्रमुख अवीव कोचावी ने घोषणा है कि उनकी फौज इरान की ओर से किए जाने वाले किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अपने हाल के बजट में इजरायल पर हमला करने के लिए धनराशि का प्रावधान किया है। इसको देखते हुए यह जरूरी है कि इजरायल भी रक्षात्मक कदम उठाए। हाल ही में इजरायली सीमा के समीप ईरानी मिलिशिया की गतिविधियां

बढ़ी हैं। इजरायल के सेना प्रमुख का कहना है कि इसे इजरायल किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। हमारे लिए इजरायल की रक्षा करना सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित 11 नवंबर के समाचार के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरानी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में एक वर्ष का विस्तार कर दिया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक सामान्य संबंध स्थापित नहीं हुए हैं इसलिए 1979 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने राष्ट्रीय आपातकाल का जो आदेश जारी किया था वह आगे भी जारी रहेगा।

इत्तेमाद (2 नवंबर) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर आजाद फिलिस्तीनी रियासत का समर्थन नहीं करेगी। हम किसी भी स्थिति में इस क्षेत्र में अलग रियासत बनाने के प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इजरायल ने जॉर्डन और मिस्र के साथ जो शांति समझौते किए थे उनका इन देशों की जनता को लाभ हुआ है। जहां तक ईरान का संबंध है उनकी सरकार ईरान के साथ युद्ध की हालत में है और हमारा शीत युद्ध चल रहा है। हाल ही में ईरान ने यूरेनियम का संवर्द्धन करने की क्षमता में जो वृद्धि की है उससे इजरायल के लिए खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इजरायल अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन करता है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजरायल के सीमावर्ती क्षेत्रों में ईरान के सहयोग से जो युद्धाभ्यास शुरू किए हैं उससे इजरायल के लिए खतरा बढ़ गया है।

सियासत (7 नवंबर) के अनुसार ईरान के परमाणु उर्जा संस्थान ने यह दावा किया है कि यूरेनियम के भंडार में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है और हमारे पास 210 ग्राम संवर्द्धित यूरेनियम मौजूद है। 2015 में ईरान और 7 देशों के बीच यह समझौता हुआ था कि ईरान न तो परमाणु अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण करेगा और न ही यूरेनियम के भंडार में वृद्धि करेगा। ईरान के परमाणु ऊर्जा के प्रवक्ता बेहरोज कमालवंडो ने कहा है कि ईरान के पास इस समय जो यूरेनियम है उससे आवश्यकता होने पर परमाणु अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण ईरान द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम परमाणु शक्ति

का इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए करना चाहते हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 नवंबर) के अनुसार इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है कि ईरान के बढ़ते हुए खतरों से निपटने के लिए उन्होंने अमेरिका से बातचीत की ह। हम यह चाहते हैं कि ईरान ने परमाणु उर्जा पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित जो समझौता किया था उसका वह पालन करे। मई 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से स्वयं को अलग कर लिया था और उसके बाद ईरान पर पुनः कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके जवाब में ईरान ने यूरेनियम संवर्द्धन के कार्यक्रम को तेज करने की घोषणा की थी।

इत्तेमाद (4 नवंबर) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम अमेरिका की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। इस क्षेत्र में अमेरिका को हर कदम पर हार हुई है और अमेरिका के इरादे कभी सफल नहीं होंगे।

इंकलाब (13 नवंबर) के अनुसार अमेरिका, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने संयुक्त रूप से समुद्र मं सैनिक अभ्यास करने की घोषणा की है। प्रवक्ता के अनुसार इसका लक्ष्य इस क्षेत्र में इरान के बढ़ते हुए खतरे का सामना करना है। पिछले वर्ष अमेरिका के दबाव पर संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इस संबंध में अब्राहम समझौता किया गया था, जिसका लक्ष्य ईरान के बढ़ते हुए खतरों का मुकाबला करना था। एक अमेरिकी बयान के अनुसार यह युद्धाभ्यास पांच दिन तक जारी रहेंगे और इसमें अमेरिका के युद्धपोत भी हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य जॉर्डन तट के समीप इजरायल के एक जलपोत पर हुए ईरानी हमले जैसी घटनाओं को रोकना है। इन अभ्यासों का उद्देश्य समुद्र में ईरान की बढ़ती हुई गतिविधियों पर लगाम लगाना है।

सऊदी अरब में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान

कौमी तंजीम (9 नवंबर) के अनुसार सऊदी अरब ने भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी अभियान तेज कर दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिकरण द्वारा 172 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 'अल अखबार' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक अधिकरण ने गत एक महीने में 6061 स्थानों पर छापे मारकर 512 व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच की जिसमें रिश्वतखोरी, फ्रॉड और पद का दुरुपयोग के आरोप में 172 सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन अधिकारियों का संबंध रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सऊदी नेशनल गार्ड और पर्यावरण आदि से बताया जाता है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ प्रमाण जुटाए जा चुके हैं। इसके बाद उनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चलाए जाएंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकारी कार्यालयों में संदिग्ध और गैरकानूनी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गुप्तचर तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है।

मुस्लिम विश्वविद्यालय से अल्लामा इकबाल का संबंध

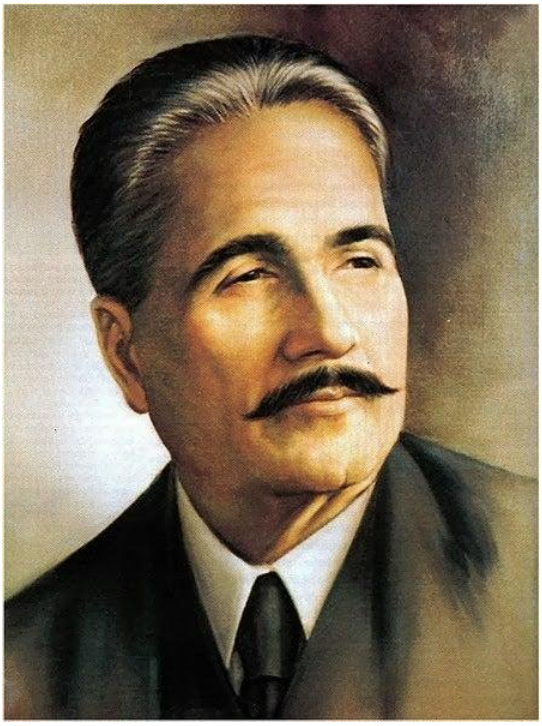

अवधनामा (11 नवंबर) के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उर्दू एकेडमी के पूर्व निदेशक डॉ. राहत अबरार के अनुसार 1906 में जब मोहम्मडन-एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के छात्रों ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था तो उस समय अल्लामा इकबाल ने उन्हें यह निर्देश दिया था कि वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन न करें और अपना ध्यान शिक्षा पर दें। राहत अबरार ने कहा कि जब मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज को विश्वविद्यालय में बदलने का अभियान शुरू हुआ तो उसमें इकबाल भी शामिल थे। उन्होंने लाहौर में इस विश्वविद्यालय के लिए 30 लाख रुपये का चंदा सर आगा खान के सहयोग से इक्ट्ठा किया था। मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए फंड इक्ट्ठा करने के उद्देश्य से इकबाल ने कई स्थानों का दौरा भी किया था। जब यह विश्वविद्यालय बन रहा था तो विश्वविद्यालय के ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य भी इकबाल ही थे। इकबाल की सेवाओं को देखते हुए विश्वविद्यालय के सचिव नवाब वकारूल मलिक ने उन्हें एमएओ कॉलेज का न्यासी भी बनाया था। वे विश्वविद्यालय के गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी रहे। इकबाल चार-पांच बार अलीगढ़ आए। 29 अप्रैल 1929 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र यूनियन की तरफ से उन्हें लाइफटाइम मेंबरशिप भी दी गई थी। इसलिए आज भी यूनियन हॉल में उनका चित्र लगा हुआ है। 1932 में उन्हें डिलीट की मानद उपाधि भी प्रदान इसी विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी।

मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोगो से संबंधित नोटिस

इत्तेमाद (11 नवंबर) के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोगो से संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्टार अब्दुल हमीद ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें 4 अक्टूबर 2005 के प्रस्ताव नंबर 15 का हवाला देते हुए कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के मोनोग्राम में कुरान की एक आयत लिखी हुई है। इसका इस्तेमाल विश्वविद्यालय से संबंधित दस्तावेजों में किया जाता है। मगर अलीगढ़ छात्र संघ ने इस लोगो को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विभिन्न स्थानों, प्रमाणपत्रों और किताबों से हटाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शित

किया था। इस पर रजिस्टार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि भविष्य में आयत वाले लोगो का इस्तेमाल नोटिस, आमंत्रण पत्रों, पर्चे, परीक्षा पत्रों और कैलेंडरों आदि में नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के इस फैसले का स्वागत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हमजा सुफियान ने किया है। इस लोगो का इस्तेमाल काफी समय से नहीं किया जा रहा था। अब तक विश्वविद्यालय के लोगो को छह बार बदला जा चुका है। अंतिम परिवर्तन 1951 में किया गया था जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उपकुलपति डॉ. जाकिर हुसैन थे। उन्होंने पुराने लोगो से ब्रिटिश ताज को हटाकर उसकी जगह कुरान की आयत को शामिल किया था।

सऊदी अरब में रोजगार का स्वदेशीकरण

सियासत (5 नवंबर) के अनुसार सऊदी सरकार सभी सरकारी कार्यालयों में सिर्फ सऊदी अरब के नागरिकों को ही नियुक्त करने का अभियान तेज कर रही है। इस अभियान का असर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों पर भी पड़ेगा। इस समय इन देशों के 60 लाख से अधिक नागरिक सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं। इससे पूर्व भी सऊदी अरब की सरकार ने नौकरियों में स्थानीय नागरिकों को ही भर्ती करने का जो फैसला किया था उसके कारण 15 लाख भारतीय नागरिकों को बोरिया-बिस्तर बांधकर स्वदेश लौटना पड़ा था। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में सऊदी अरब में नौकरी करने वाले व्यक्तियों की महत्त्वपूण भूमिका है। क्योंकि वे हर महीने करोड़ों रियाल भारत भेजते हैं। सऊदी अरब की इस नई नीति का प्रभाव मुख्य रूप से केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इन राज्यों के निवासी अगर बेरोजगार होकर स्वदेश लौटते हैं तो उनका पुनर्वास राज्य सरकारों के लिए काफी जटिल समस्या बनेगी।

9540729392

बढ़ती आबादी के लिए मुल्क के मदरसे जिम्मेवार

अखबार-ए-मशरिक (12 नवंबर) के अनुसार अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरि ने देवबंद पहुंचकर देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए मदरसों को अपना निशाना बनाया है। उन्होंने वहां पर आरोप लगाया कि इस्लामिक मदरसे जनसंख्या में वृद्धि को प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनका लक्ष्य देश के लोकतंत्र पर कब्जा करना है। इसलिए बहुसंख्यकों को इस साजिश से होशियार रहना चाहिए। उन्होंने देवबंद में एटीएस सेंटर की स्थापना के सरकारी फैसले की प्रशंसा की और कहा कि जब तक दारूल उलूम और मदरसों को समाप्त नहीं किया जाता तब तक इन एटीएस केन्द्रों का कोई लाभ नहीं होगा। स्वामी नरसिंहानंद गिरि के देवबंद पहुंचने पर स्थानीय हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी द्वारा डासना मंदिर में पूजा करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जो पुस्तक लिखी है उसका मंदिर में विमोचन किया जाएगा। यह किताब मुसलमानों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे सनातन धर्म के प्रचारक हैं और अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं।

बलात्कार के आरोपी को नपुंसक बनाना इस्लाम के खिलाफ

कौमी तंजीम (29 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान की इस्लामिक विचारधारा परिषद ने पाकिस्तान के फौजदारी संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत बलात्कार के आरोपी को नपुंसक बनाने के कानून को गैर इस्लामिक घोषित किया है। परिषद के अध्यक्ष डॉ. किबला अयाज ने यह मत व्यक्त किया है कि इस सजा के स्थान पर अन्य सजा देने पर विचार किया जाए। क्योंकि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार किसी व्यक्ति को नपुंसक बनाना शरिया के खिलाफ है। परिषद ने पाकिस्तान के शिक्षा संस्थानों में अरबी को अनिवार्य विषय बनाने का समर्थन किया है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

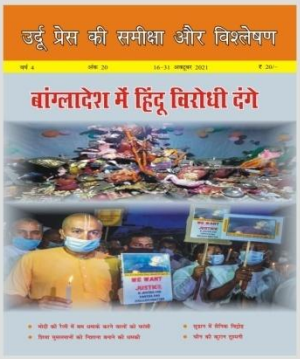

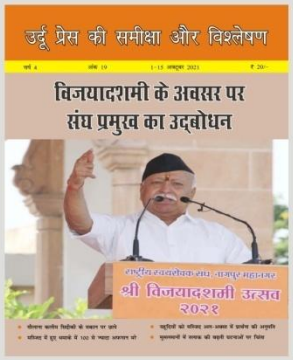

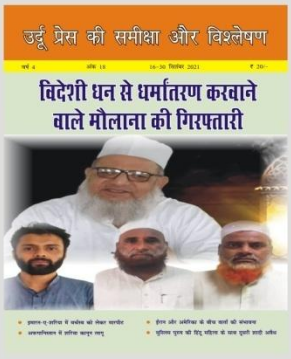

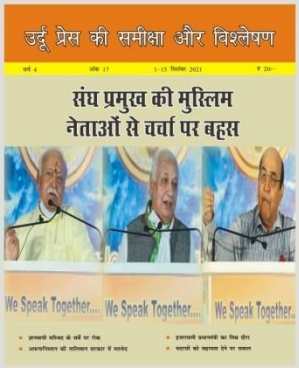

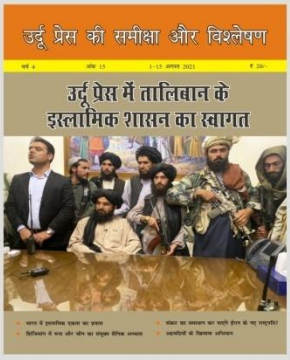

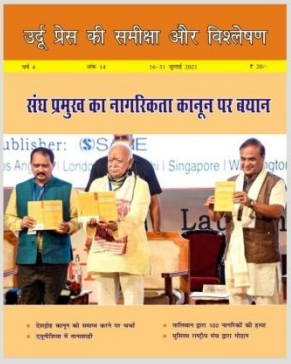

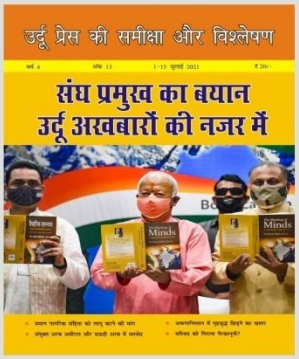

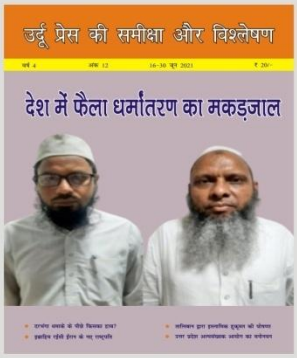

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रतीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in